ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-12*January- 2022
Innovation The Research Concept

डिजिटल इण्डिया
Digital India

Paper id: 15577 Submission: 11/01/2022, Date of Acceptance: 21/01/2022, Date of Publication: 23/01/2022

ज्योति सोनी
सहायक प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
पी.डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़,
छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

आज देश में डिजिटल बुनियादी ढ़ाचे का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल इंडिया ने पिछले पांच वर्षों में पर्याप्त सफलता हासिल की है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान अधिकांश भारतीय आबादी ने भौतिक नकद भुगतान की जगह डिजिटल भुगतान को अपना लिया है। छोटे बड़े सभी व्यवसाय कर्ताओं द्वारा डिजिटल तकनीकों को अपना लिया गया है। व्यवसायी बिना किसी परेशानी के आनलॉइन माध्यमों का उपयोग कर व्यवसाय संचालित कर रहे है। डिजिटल भागीदारी के कारण डॉक्टरों के साथ आनॅलाइन चिकित्सा परामर्ष संभव हो पाया तथा प्राथमिक और उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थान डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके ही निर्बाध आनलॉइन षिक्षण प्रदान कर पा रहे है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भारत अपने नागरिकों की आकांक्षओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लम्बे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिषा में योगदान कर सकें।

Today there is an urgent need to create digital infrastructure in the country. Digital India has achieved substantial success in the last five years. Most of the Indian population has adopted digital payments instead of physical cash payments, especially during the corona pandemic. Digital technologies have been adopted by all businesses, big and small. Businessmen are conducting business using online mediums without any hassle. Online medical consultation with doctors has become possible due to digital partnership and primary and higher education institutions are able to provide seamless online education using digital services. Through the Digital India program, India is committed to fulfill the aspirations of its citizens so that the government and its services are available at the doorsteps of the citizens and contribute towards a long-term positive impact.

मुख्य शब्दः डिजिटल इण्डिया, समय श्रम धन की बचत, सशक्तिकरण।
Keywords: Digital India, Saving Time Labor Money, Empowerment.

प्रस्तावना

सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम नवीन क्रांति की शुरूआत करेगा।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम वास्तव में भारत सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें बहुत से सरकारी मंत्रालय व सरकारी विभाग सम्मिलित है। यह वास्तव में अनेक विचारों को एक कर, देश को विकास के मार्ग पर ले जाने वाली योजना है।

डिजिटल इण्डिया अर्थात्-

1. सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच
2. पारदर्शी भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट
3. समय श्रम धन की बचत
4. तेजी से लाभए पूरा लाभ
5. Minimum Government, Maximum Governance

डिजिटल इण्डिया मिशन का प्रारम्भ जुलाई 1 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। डिजिटल इण्डिया मिशन के लोगो का डिजाईन राणा भौमिक द्वारा किया गया। लोगो के डिजाईन का आधार नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर डिजिटल युग की गति और भारत के स्वाद को प्रतिबिंबित करना था। इसलिए यह लोगो सफलतापूर्वक राष्ट्रीय रंगों के साथ D एण्ड I को जोड़ता है। डिजिटल इण्डिया के वास्तुकार रविशंकर प्रसाद, एस एस, आहलुवालिया है। डिजिटल इण्डिया का घ्येय वाक्य “power to empower” है।

डिजिटल इण्डिया एक सषक्त तकनीक समाधान है जो वर्षों से बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण में सहायक रहा है। आज यह स्टार्टअपए डिजिटल शिक्षा, निर्बाध बैंकिंग एवम् भुगतान समाधानए एग्रीटेक, स्वास्थ्य, तकनीक, स्मार्ट सिटीज्, ई शासन, खुदरा प्रबंधन जैसे उभरते क्षेत्रों के आधार के रूप में काम कर रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

डिजिटल इण्डिया सरकारी विभागों एवम् भारत के लोगों कोए एक दूसरे के पास लाने की सरकारी पहल है। डिजिटल इण्डिया के तहत सभी सरकारी सुविधाओं को इण्टरनेट से जोड़ने का काम किया गया है। इसका उद्देश्य

1. भारत को एक ज्ञान भविष्य हेतु तैयार करना,

2. परिवर्तन को साकार करना अर्थात् इण्डियन टैलेंट (IT) + इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी (IT) + इण्डिया टूमारो (IT) को वास्तविक रूप देना,
3. परिवर्तन को सक्षम करने प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय बनाना। एक शीर्ष कार्यक्रम बनाना जो कई विभागों तक पहुंचे।

दृष्टि क्षेत्र डिजिटल इण्डिया का विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है-

प्रत्येक नागरिक के लिए इन्फ्रास्टक्चर एक उपयोगिता के रूप में।
1. उच्च गति का इण्टरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराना।
2. जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान
3. सुरक्षित साईबर स्पेस
4. कॉमन सर्विस सेंटर खोलना
5. पब्लिक क्लॉउड पर साझा करने योग्य निजी जगह

मांग पर प्रषासन और सेवाए
1. सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में परिणित करना
2. एक सीमा से अधिक वित्तिय लेनदेन को इलेक्ट्रानिक और कैशलेस बनाना
3. विभागों में एकल खिड़की द्वारा कई व्यक्तियों की आसान पहुंच
4. क्लाउड पर सभी नागरिक पात्रताओं की आसान पहुंच

नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
1. युनिवर्सल डिजिटल साक्षरता
2. भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों एवम् सेवाओं की उपलब्धता
3. सभी डिजिटल संसाधन सर्वत्र सुलभ
4. क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों की सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी

डिजिटल इण्डिया के नौ स्तम्भ

ब्रॉडबैंड हाइवे सड़क हाईवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाइवे शहरों को जोड़ा जायेगा।

मोबाईल कनेक्टिवीटी तक सार्वजनिक पहुंच सभी नागरिकों की टेलिफोन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जावेगी।

मोबाईल कनेक्टिवीटी तक सार्वजनिक पहुंच सभी नागरिकों की टेलिफोन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जावेगी।

पब्लिक इण्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम इसके तहत सार्वजनिक रूप में इण्टरनेट सेवाऐ उपलब्ध कराई जायेंगी।

ई षासन इस तकनीक में प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन व्यवस्था में सुधार लाया जायेगा।

ई क्रांति लोगों को विभिन्न सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलिवरी प्रदान की जावेगी।

इन्फार्मेषन फॉर ऑल अर्थात् सभी को सूचना उपलब्ध कराई जावेगी।

इलेक्ट्रानिक्स वी निर्माण इलेक्ट्रानिक उत्पादन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रानिक उत्पादों हेतु कलपुर्जों के आयात को शून्य करना है।

नौकरियों के लिए आई टी आई टी यानि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नौकरियों हेतु अवसर प्रदान करना।

अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इस कार्यक्रम का संबंध स्कूल, कॉलेजों में विद्यार्थी एव शिक्षकों की उपस्थिति से है।

कार्यक्रम प्रबंधन संरचना डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक कार्यक्रम प्रबंधन संरचना स्थापित की गई। प्रबंधन संरचना के मुख्य घटक में परियोजनाओं को अनुमोदन देने हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समितिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निगरानी समिति सूचना एवम् प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इण्डिया का सलाहकार समूह, केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति आदि का गठन किया।

डिजिटल इण्डिया निगरानी समिति के सदस्य	प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), वित्त मंत्री, सूचना एवम् प्रौद्योगिकी मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रीए शहरी एवम् ग्रामीण विकास मंत्री, स्वास्थय मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, व्यय योजना टेलीकॉम व कार्मिक सचिव, विशेष आमंत्रित सदस्यए सूचना सचिव कमेटी के संयोजक।

डिजिटल इण्डिया की उपलब्धियॉं

डिजी लॉकर	यह प्रणाली प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी किये गये आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहित करने, एक ऑनलाईन भण्डारण स्थान प्रदान करता है। विद्यार्थी दस्तावेजों को डिजिलॉकर पर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी प्लेटफार्म के जरिए अपलोड कर सकता है। इससे डाक्यूमेंट वैरिफिकेशन आसान हो जायेगा। एनएडी शैक्षणिक डिग्रियों को आनॅलाइन सुरक्षित रखने का 24/7 स्टोर हाउस हैं। विद्यार्थी अपने प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आनॅलाइन स्टोर कर सकते है। कोविड-19 के खतरे के बीच ऑनलाइन डाक्यूमेंट वैरिफिकेशन से विद्याथियों को यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा इससे फर्जी डॉक्यूमेंटस् का जोखिम भी खत्म हो जायेगा।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल	(एक वेबसाईट के अंतर्गत सभी छात्रवृत्ति) यह योजना छात्रवृत्ति को लाभार्थियों के खाते में धन के वितरण को प्रभावी बनाने व तेजी से भेजने में मदद करती है। इस वेबसाईट में विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रालयों सरकारों व अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए आवेदन व पंजीकरण किया जा सकता हैं।
PM-WANI योजना	इस योजना के तहत देश भर में ऐसे Access points बनाये जा रहे हैं जहाँ कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड WIFI इण्टरनेट उपलब्ध हो सके जिससे गरीब परिवार के बच्चों युवाओं को ऑनलाईन शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके।
ई-साईन	इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर द्वारा एक आधार कार्ड धारक अपने दस्तावेजों को ऑनलाईन हस्ताक्षरित करा सकता है।
डिजिटाईज्ड इण्डिया प्लेटफार्म	(DIP) रिकॉर्ड कमरे एवम् कार्यालयों के कागजात के ढ़ेर को कम करने हेतु भौतिक अभिलेखों को डिजिटाईज्ड करना।
डिजिटल हेल्थ कार्ड	देश की जनता को स्वास्थ्य अधिकार देने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सितम्बर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारम्भ किया इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड दिया जावेगा जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी सम्पूर्ण रिकॉर्ड दर्ज होगा।
UDID कार्ड	इस कार्ड में दिव्यांगों को यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी दिया जाता है जिससे दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र लेकर घुमना नहीं पड़ता। इस कार्ड से दिव्यांगजन देश भर में अपनी पहचान बताकर कहीं भी इलाज करा सकते हैं।
ई हास्पिटल, ऑनलाईन पंजीकरण प्रणाली, ऑनलाईन लैब रिपोर्ट, ई ब्लड बैंक	जैसी सुविधाए मरीजों, डॉक्टरों, अस्पतालों को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर जोड़ने में मदद करता है।
स्वच्छ भारत मिषन एप	लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक करने व स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विभिन्न काय्रक्रमों से जुड़ने को प्रेरित करने हेतु यह एप विकसित किया गया हैं
ई गवर्नेन्स	देश के नागरिकों को सरकारी सूचना व सेवाए प्रदान करने हेतु संचार एवम् सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना।
MyGov ऐप	डिजिटल इण्डिया के तहत बनाये गये माई गॉव एप के द्वारा नागरिक अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, विभिन्न मुद्दों व समस्याओं पर अपना मत प्रकट कर सकते हैं।
One Nation One Ration card	ये डिजिटल इण्डिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब काम हेतु दूसरे राज्य में जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होती।
स्वनिधि योजना	रेहड़ी ठेला पटरी वालों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ बैंक से आसान व सस्ते ऋण की उपलब्धता।

स्वामित्व योजना

डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को उनके घर की कानूनी सुरक्षा का दस्तावेज देने हेतु गॉव की जमीनों की ड्रोन मैपिंग करवाना।

डिजिटल **Contact Tracing App** में से एक आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण को रोकने में अत्यंत सफलता मिली। टीकाकारण हेतु COWIN App भी लोकप्रिय रहा। Vaccination की प्रक्रिया के लिए ऐसा Monitoring tool होना हमारी तकनीकी कुषलता का प्रमाण है।

One Nation One Data

डिजिटाइजेशन के दौर में अब देष वन नेशन वन डेटा के लिए तैयार हो रहा है। संकेत है कि 2022 में जनगणना शुरू होने से पहले नया कानून अमल में आ जाएगा। संशोधन पश्चात् एक ही तारीख पर हर राज्य में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। नया कानून लागू होने के बाद न सिर्फ जन्म मृत्यु का पूरा डेटा केन्द्रीय स्तर पर जमा होने लगेगा बल्कि इस डेटा के आधार एनपीआर आधार ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत दूसरे डेटाबेस भी अपडेट हो जाएगें। नए कानून के बाद सम्पूर्ण देष में जन्म मृत्यु पंजीयन का फार्मेट एक हो जाएगा। इसका सीधा लाभ यह होगा कि केन्द्रीय योजनाओं के पात्र लोगों की मॉनिटरिंग केन्द्रीय स्तर पर हो जाएगी।

यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड

यह योजना संचार मंत्रालय के डाक विभाग की है। पिन कोड की जगह लेने वाला यह डिजिटल एड्रस कोड (12 डिजिट का यूनिक कोड) हर भवन के लिए डिजिटल को-ऑर्डिनेट्स की तरह काम करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के हर पते को डिजिटल अर्थात् प्रमाणीकरण करना है। इससे हर तरह के सामान की सही पते पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी। जो भी प्लेटफार्म डिजिटल मैप के जरिए डिलीवरी के लिए पते को लोकेट करते है वे डीएसी के जरिए इसे सटिक बना सकते है। इससे हर घर का आनॅलाइन एडेस वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। बैंकिग बीमा और टेलीकॉम के लिए एड्रस का प्रमाणपत्र नही देना होगा। यह एक तरह से ई-केवाईसी के तौर पर काम करेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेशन, आपदा प्रबंधन, आपात सेवाओं, चुनाव प्रबंधन और जनगणना एवम् जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने में आसानी होगी।

भारत की सास कंपनियॉ बदल रही डिजिटल दुनिया

SAAS अर्थात् सास जिसे मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अर्थात् सेवा के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इसकी डिजिटाइजेशन में बहुत ज्यादा सम्भावनाऐं हैं। सास वे कम्पनियॉ है जो वेबसाइट ऐप ईमेल एसएमएस क्लाउड स्टोरेज साइबर रिस्क ई आर पी सी आर एम डिजिटल मार्केटिंग और एआई समाधन जैसी डिजिटल सेवाऐं प्रदान करती है। लॉकडाउन के दौरान हर व्यवसाय शैक्षिणक संस्थान चिकित्सा संस्थान और उपभोक्ता की ओर से वांछित डिजिटल इंफ्रास्टक्चर की मांग बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि सास कंपनियों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है।

डिजिटल मोड पर चुनावी प्रचार

कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनावी राज्यों में सियासी संग्राम का डिजिटल मोड पर होना डिजिटल इण्डिया अभियान की सफलता को दर्षाता हैं। उन्नत उपकरणों से लैस डिजिटल फोर्स रूम बनाकर आई आई एम, आई आई टी पासआउट प्रोफेशनल्स के जरिए डिजिटल मैराथन जैसे अभियान की योजना बनाई जा रही है। कोराना काल में सभी चुनावी पार्टियों का वर्चुअल प्रचार के लिए तैयार होना बड़ी उपलब्धि है।

बिजनेस में डिजिटल तकनीक का समावेष

डिजिटल तकनीक के समावेश से अनेक उत्पाद स्मार्ट हो सेवा में बदल रहे है। इसलिए कई सारे बिजनेस टू बिजनेस उत्पाद के तौर पर बिजनेस टू कस्टमर में परिवर्तित हो जाएगें। अंततः ऑगमेंटेड रिएलिटी और वर्चुअल रिएलिटी के इस्तेमाल से हम उत्पाद और सेवा प्रदाता की उपभोक्ता से करीबी देखेंगें।

डिजिटल इण्डिया की चुनौतियॉ

1. ऐसे गॉव जहॉ बिजली की सुविधा नहीं वहॉं इण्टरनेट की सुविधा पहुंचाना अत्यंत कठिन है।
2. ब्रॉडबैण्ड हाईवे की षुरूआत ऑप्टिक फाईबर नेटवर्क से होती है, गॉवों तक फाईबर नेटवर्क का तार बिछाना सबसे बड़ी चुनौती है।
3. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जैसे मुद्दों का उचित समाधान खोजना
4. तकनीकी कौशल, भाषा ज्ञान, शिक्षा के स्तर में कमी नजरअंदाज कर डिजिटल इण्डिया निर्माण लक्ष्य को प्राप्त करना।
5. विभाग डिजिटल होने के बावजूद कर्मचारी अभ्यस्त नहीं होते इसलिए सरकारी विभागी कार्यवाही को डिजिटल बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य है।
6. आयूष्मान डिजिटल मिषन के क्रियांवयन में भी कई चुनौतियॉ है। चिकित्सा प्रदाता की मानसिकता नुस्खे व रोगी के स्वास्थ्य रिकार्ड पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने की अनिच्छा इस मिशन की सफलता में प्रमुख बाधा होगी। अस्पतालों विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों के कार्य में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता होगी। सभी हितधारकों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाना मिषन के लिए एक प्रमुख चुनौती है। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य अभिलेखों का प्रमाणीकरण क्रास चेकिंग और डेटा का प्रमाणीकरण करना आवशयक होगा अन्यथा एक छोटी सी चुक से पूर्ण योजना विफल हो सकती है। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य डेटा तक आसान पहूॅच से कई अनैतिक कृत्य हो सकते है। सख्त साइबर कानून लागू करने होगें।
7. सास कम्पनियॉ नए उत्पादों और जरूरतों के मुताबिक सेवाओं की पेशकश कर रही है लेकिन कुछ समस्यायें भी हो सकती है। जैसे- सास सॉफ्टवेयर सेवाऐं बहुत हद तक इंटरनेट आधारित है। इन

सेवाओं को बिना किसी रूकावट के प्राप्त करने हेतु उच्च बैंडविड्थ वाला इंटरनेट कनेक्षन होना जरूरी है। व्यापार संबंधी डेटा के चोरी होने व प्राइवेसी पर संकट की आशका भी सदैव बनी रहती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से डिजिटल इण्डिया के लिए नया नारा दिया थाए नकद को ना डिजिटल पेमेंट को हाँ।
कोविड 19 महामारी के दौर में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के कारण ही अपने घर से काम करने डिजिटल पेमेंट प्राप्त करने डिजिटल पेमेंट देने छात्र टीवी मोबाईल लैपटॉप से शिक्षा पाने मरीज ऑनलाईन डॉक्टरों की सलाह लेने तथा किसान अपने बैंक खाते में सीधे राशि प्राप्त करने में सक्षम हुए । ड्राईविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट पैन कार्ड रेल्वे टिकिट रेल्वे पास एयर टिकिट बिजली पानी का बिल राशन का बिल इनकम टैक्स रिटर्न भरना आदि विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया डिजिटल इण्डिया के माध्यम से आसान व सरल हो गई। डिजिटल इण्डिया अभियान में Infrastructure के Scale speed और High speed दोनों पर बहुत ध्यान दिया गया। Common service centre ने इण्टरनेट को वहाँ भी पहुंचाया जहाँ ये मुश्किल माना जाता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Digital India Wikipedia*
2. *www.aajtak.in*
3. *Dainik Bhaskar newspaper*
4. *Patrika newspaper*
5. *Pratiyogita Darpan Magazine*
6. *www.sarkariyojana.co.in*